डॉ सज्जन सिंह यादव

# चार स्तंभों से सशक्त होता विकसित भारत

***2026-27 का बजट चार स्तंभों - युवा, महिलाएं, किसान और गरीब पर आधारित है। ये स्तंभ विकसित भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक ढांचा बनाते हैं। अगर भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल होना है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका जनसांख्यिकीय लाभांश (युवा) कौशल-युक्त हो, उसकी खेती की रीढ़ (किसान) उन्नत हो, इस्तेमाल से वंचित उसकी श्रम क्षमता (महिलाओं) का लाभ प्राप्त हो, और इसका सबसे कमजोर हिस्सा (गरीब) सिस्टम के झटकों से सुरक्षित रहें।***

आज, वैश्विक मंच पर भारत की शानदार उपस्थिति है। हम दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उद्यमियों की एक नई पीढ़ी हमारे उद्योगों को नया आकार दे रही है। डिजिटल पब्लिक सिस्टम के बल पर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के तरीके बदल रहे हैं।

फिर भी, देश के सामने चुनौतियां उतनी ही बड़ी हैं। हर साल, लाखों युवा बड़ी उम्मीदों के साथ श्रम बाज़ार में आते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश करने की जरूरत है। देश को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिमों का ध्यान रखते हुए उपायों को मजबूत करना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2026 को, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। उनके लगातार नौवें बजट के तौर पर, यह भारत की आर्थिक नीति के निर्माण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। बजट ने देश की ख़ास ताकतों और सबसे बड़ी चुनौतियों, दोनों को साफ तौर पर पहचाना, और उन्हें हल करने के लिए एक साफ़ और सटीक रणनीति बनाई।

## विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ

2026-27 का बजट चार स्तंभों : युवा, महिलाएं, किसान और गरीब को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये स्तंभ विकसित भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक ढांचे का निर्माण करते हैं। अगर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना है, तो उसे यह पक्का करना होगा कि उसका जनसांख्यिकीय लाभांश (युवा) स्किल्ड हो, उसकी खेती की रीढ़ (किसान) उन्नत हो, इस्तेमाल से वंचित उसकी श्रम क्षमता (महिलाओं) का योगदान सुनिश्चित हो, और उसके सबसे कमजोर (गरीब) लोग सिस्टम के झटकों से सुरक्षित रहें।

आइए अब इन सभी स्तंभों को क़रीब से देखें और समझें कि बजट कैसे उनका समर्थन करता है।

## युवा

वृद्धावस्था की ओर तेजी से बढ़ती दुनिया में, भारत युवाओं के देश के रूप में स्थापित है। देश की बड़ी युवा आबादी इसका सबसे ताकतवर आर्थिक तंत्र है। इसका फायदा उठाने के लिए, जनसांख्यिकीय लाभांश को एक लाभदायक कार्यबल में बदलने की जरूरत है और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना होगा।

इसे सपोर्ट करने के लिए, 2026-27 के राजकोषीय रोडमैप में कौशल प्रदान करने, नियोजनीयता बढ़ाने, आसान ऋण तक पहुंच प्रदान करने और उद्यमशीलता का वातावरण तैयार करने पर ख़ास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने संभावना और समृद्धि के बीच एक मजबूत कड़ी बनाने की योजना इस तरह बनाई है।

- **नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप**

बजट में बड़े औद्योगिक गलियारे के पास पांच नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव है। ये संस्थान विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे और शिक्षा जगत तथा उद्योग जगत के बीच लंबे समय से चली आ रही खाई को भी पाटेंगे। सरकार का मकसद छात्रों को औद्योगिक केंद्र में रखते हुए, बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार,

*लेखक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं। ईमेलः authorsajjan@gmail.com*

शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना है, ताकि प्रयोगशाला से धरातल तक नवाचार की संस्कृति आगे बढ़े।

- **सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को बढ़ावा**

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर अच्छी तरह से इसकी देखभाल की जाए, तो स्टार्टअप और एमएसएमई भारत के आर्थिक विकास के अगले इंजन बन सकते हैं। ये लाखों युवाओं को रोज़गार देते हैं। हालांकि, कई एमएसएमई वित्त, प्रौद्योगिकी और बाज़ार तक सीमित पहुंच के कारण आगे बढ़ने में संघर्ष करते हैं।

वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक नए एमएसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा की। इसका मकसद मापनयोग्य इकाइयों की पहचान करना और उन्हें चैंपियन एमएसएमई बनाना है, यानी ऐसी कंपनियां जिनके पास वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने के लिए आकार और उन्नत संसाधन हो।

- **सूक्ष्म उद्यमों के लिए अधिक जोखिम पूंजी**

सूक्ष्म उद्यमों के लिए, शुरुआती चरण में अक्सर अपना अस्तित्व कायम रखना कठिन होता है। यह बजट सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड में अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये डालकर आधारभूत उद्यमशीलता को मजबूत करता है। इसके अलावा, सरकार ने एंजेल टैक्स को खत्म करने का क़दम उठाया है, जिससे एक बड़ी नियामक बाधा दूर हुई है। इन दोनों उपायों से घरेलू निवेश और आधारभूत नवाचार के लिए और भी अधिक अनुकूल वातावरण बनेगा।

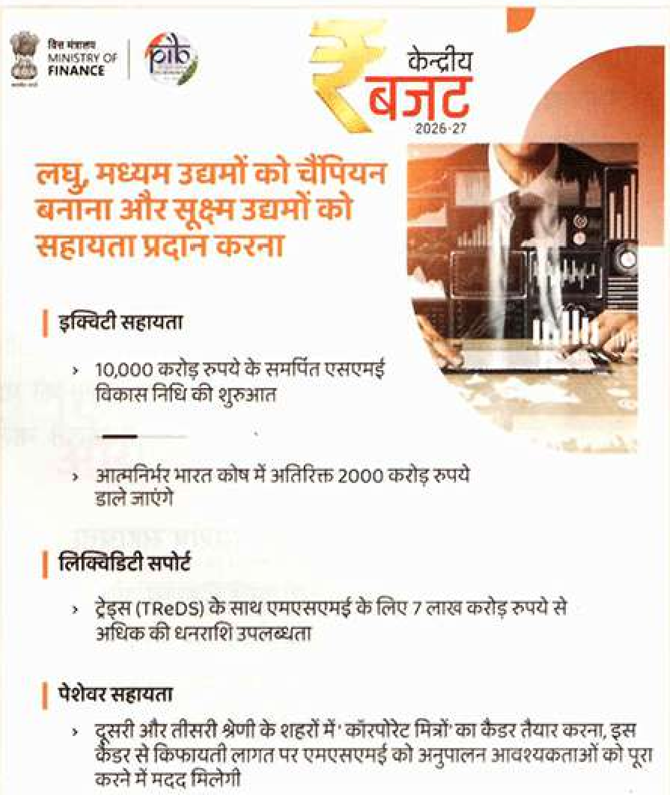


- **कॉरपोरेट मित्र**

इस बजट में सबसे नए प्रस्तावों में से एक कॉरपोरेट मित्र पहल है। सरकार युवाओं को कॉरपोरेट मित्र के तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई), और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) जैसे पेशेवर संस्थाओं के साथ साझेदारी करेगी।

ये मित्र एमएसएमई को जीएसटी, अनुपालन, बुककीपिंग और बेसिक फाइलिंग पर, ख़ासकर टियर-II और टियर-III शहरों में, सस्ती सलाह देंगे। इससे दो मकसद पूरे होंगे: युवा पेशेवरों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले रोज़गार तैयार करना और छोटे कारोबार के लिए कार्य करना आसान बनाना।

- **ऑरेंज इकोनॉमी: कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा**

यह मानते हुए कि भविष्य के करियर तेजी से डिजिटल और क्रिएटिव होते जा रहे हैं, बजट में ऑरेंज इकोनॉमी पर बड़ा दांव लगाया गया है। वित्त मंत्री ने 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) लैब बनाने की घोषणा की है। ये ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मीडिया मार्केट में नेतृत्व करने के लिए सक्षम कार्यबल तैयार करेंगे।

- **पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में रोज़गार**

पर्यटन में, ख़ासकर युवाओं और लोकल कम्युनिटी के लिए रोज़गार पैदा करने की बहुत अधिक संभावना है। पर्यटन मंत्रालय 10,000 टूरिस्ट गाइड को प्रशिक्षण प्रदान करके उनका कौशल बढ़ाएगा। इस सेक्टर में पेशेवर प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी भी बनाया जाएगा।

ख़ास और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बजट में माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स और बर्ड-वॉचिंग ट्रेल्स बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 15 पुरातत्व स्थलों को एक्सपीरिएंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन में बदला जाएगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और मास टूरिज्म से पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्री ने डेडिकेटेड मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब बनाने का भी ऐलान किया है। इनका उद्देश्य ग्लोबल हेल्थकेयर मार्केट का बड़ा हिस्सा हासिल करना है, साथ ही युवाओं को वेलनेस और मेडिकल सेक्टर में उच्च कुशल वाले रोज़गार के मौके भी देना है।

- **नए युग के तकनीकी कौशल**

आने वाले कल के रोज़गार के लिए बहुत अलग कौशल की आवश्यकता होगी। इस सच्चाई को समझते हुए, बजट में आर्टिफ़िशियल

इंटेलिजेंस (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल सेवाएं और दूसरी नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। इससे युवाओं को इन तेज़ी से बढ़ते क्षेत्र में करियर के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। यह तरीका भारत के उन्नत विनिर्माण, डिजिटल सेवाएं, क्रिएटिव इकोनॉमी और एआई द्वारा संचालित नवाचार की ओर बड़े बदलाव के साथ मेल खाता है।

- **शिक्षा और रोज़गार के बीच सेतु निर्माण**

बजट एक ऐसे मॉडल को आगे बढ़ाता है जिसमें उच्च शिक्षा से न केवल छात्रों को प्रवेश करने की उम्मीद है, बल्कि रोज़गार पाने लायक ग्रेजुएट भी तैयार करने, प्रयोग आधारित अनुसंधान को मजबूत करने और नवाचार क्षमता का निर्माण होने की भी उम्मीद है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई जाएगी। यह समिति जो शिक्षण और काम के बीच की खाई को पाटने वाले सुधारों की सलाह देगी, ख़ासकर सेवा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी और उन क्षेत्रों में जहां कुशल प्रतिभाओं की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है।

## महिलाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। यह अवधारणा सामाजिक नीति के हाशिये से निकलकर भारत की आर्थिक रणनीति के केंद्र में आ गई है। बजट 2026-27 महिलाओं की शिक्षा, उद्यमिता, श्रमबल की भागीदारी और आर्थिक नेतृत्व का समर्थन करके इस विजन को आगे बढ़ाता है। इसके लिए बजट में कई जरूरी पहल की घोषणा की गई है।

- **शी मार्ट:**

महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह भारत में कुछ सबसे असरदार जमीनी आर्थिक संस्था के तौर पर उभरे हैं। लखपति दीदी जैसी पहल ने पहले ही कई ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय आत्मनिर्भरता और सामाजिक तौर पर सशक्त बनने में मदद की है।

इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, वित्त मंत्री ने पूरे देश में सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर (शी) मार्ट शुरू करने की घोषणा की है। हर जिले में कम्युनिटी के रिटेल हब के तौर पर ये आउटलेट स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों तक बाज़ार पहुंच को बेहतर बनाएंगे।

- **देखभालकर्ताओं की एक सशक्त सेना तैयार करना**

बजट में बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों की देखभाल और उससे जुड़ी स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र में ट्रेंड देखभालकर्ताओं की बढ़ती मांग को भी माना गया है। 1.5 लाख मल्टी-स्किल्ड केयरगिवर को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे ख़ासकर महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर तैयार होंगे। ये देखभालकर्ता भारत और विदेशों में बुजुर्ग आबादी को उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने में भी मदद करेंगे।

- **हर जिले में बालिका छात्रावास**

उच्च शिक्षा, ख़ासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण और गणित (एसटीईएम) विषयों में आगे बढ़ने की चाहत रखने वाली कई युवतियों के लिए सुरक्षित रहने की जगह तक पहुंच एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। इस चुनौती से निपटने के लिए, बजट में हर जिले में, ख़ासकर उच्च शिक्षा एसटीईएम इंस्टीट्यूशन में ख़ास महिला छात्रावास बनाने का प्रस्ताव है। ये सुरक्षित और आसानी से मिलने वाली रहने की जगहें महिलाओं के प्रवेश और निरंतर पढ़ाई को बेहतर बनाने में मदद करेंगी, जिससे अधिक संख्या में युवतियां उन्नत शिक्षा और पेशेवर करियर बना पाएंगी।

- **महिला-नेतृत्व वाले समूहों को मत्स्य क्षेत्र और तटीय आजीविका से जोड़ना**

बजट में मछली पालन और समुद्रतटीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अहम भूमिका को स्वीकार किया गया है। मार्केट लिंकेज और वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है, जिसमें स्टार्ट-अप, महिलाओं के ग्रुप और मछली पालने वाले उत्पादक संगठन शामिल हैं।

- **महिला-प्रधान पारंपरिक क्षेत्रों को विशेष सहायता**

बजट में भारत की सांस्कृतिक धुरी यानी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पर भी ध्यान दिया गया है। इस सेक्टर में अभी भी महिलाओं का बहुत अधिक दबदबा है। इन सेक्टर को मजबूत करने के लिए, बजट में नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के माध्यम से विशेष समर्थन का प्रस्ताव है।

इसके साथ महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल है, जिसका मकसद खादी और पारंपरिक क्राफ्ट को दुनिया भर के लोगों के लिए रीब्रांड करना है। बेहतर प्रशिक्षण, कौशल विकास, गुणवत्ता में सुधार, ब्रांडिंग और दुनिया भर के मार्केट तक पहुंच के जरिए इसका समर्थन किया जाएगा।

### किसान

भारत के तेजी से औद्योगिकरण और इसके सेवा क्षेत्र के बढ़ने के बावजूद, खेती देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। यह करोड़ों की संख्या में भारतीयों को आजीविका देती है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से आबादी के एक बड़े हिस्से का समर्थन करती है।

हालांकि, यह सेक्टर अभी जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ताओं की पसंद में बदलाव और बाधायुक्त प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके अलावा, लगभग 86 प्रतिशत किसान छोटी, मामूली जमीन पर काम करते हैं।

इसके अलावा, मात्रा आधारित, मुख्य फसलों पर अत्यधिक निर्भर पारंपरिक कृषि मॉडल अपनी सीमा तक पहुंच गया है। इस सेक्टर को उच्च-मूल्य, विविधीकृत और प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित खेती की ओर बदलाव की जरूरत है।

बजट उत्पादकता बढ़ाने, फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर फोकस करता है। इसके लिए, वित्त मंत्री ने खेती के माहौल को आधुनिक बनाने के लिए कई लक्षित क्रियाकलाप का प्रस्ताव दिया है।

- **किसानों के लिए 'भारत-विस्तार' एआई टूल**

सबसे आगे की सोच वाली पहल में से एक 'भारत-विस्तार' (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज) है, जो एक बहुभाषी, एआई-संचालित कृषि प्लेटफॉर्म है। एग्री स्टैक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) की सलाह प्रणाली से बड़े डेटा सेट को सिंथेसाइज करके, यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी जेब में एक डिजिटल सलाहकार देता है।

तत्क्षण और बहुभाषी मार्गदर्शन के जरिए, किसान सही फसलें चुन पाएंगे, कीड़ों को ज़्यादा असरदार तरीके से मैनेज कर पाएंगे, पैदावार बढ़ा पाएंगे और अपनी उपज को बाज़ारों से जोड़ पाएंगे। इस तरह, यह जानकारी को पानी या उर्वरक जितना ही जरूरी, खेती के मुख्य इनपुट में बदल देगा।

- **अधिक मूल्य और विविधीकृत खेती को समर्थन**

चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलों पर भारत की बहुत ज़्यादा निर्भरता की वजह से अक्सर बाज़ार में ज़्यादा सामान आ जाता है और परिस्थितिकीय तनाव पैदा होता है। बजट अधिक मूल्य और विविधीकृत खेती को बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान करता है। पहाड़ी इलाकों में नारियल, कोको, काजू, चंदन और अखरोट जैसी फसलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पेड़ों वाली फसलों को प्राथमिकता दी गई है।

यह रणनीति दो तरह की है। पहला, ये फसलें पारंपरिक अनाज की तुलना में प्रति एकड़ काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देती हैं। दूसरा, ये वैश्विक प्रसंस्करण और निर्यात बाज़ार के लिए कच्चे माल का काम करती हैं।

- **पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा**

जलवायु की अनिश्चितता के इस दौर में, एक मजबूत डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर रोज़ाना स्थिर नकद आय देता है, जिसकी मौसमी फसल की खेती में अक्सर कमी होती है। बजट पशुपालन के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, डेयरी और पोल्ट्री यूनिट के आधुनिकीकरण, बेहतर पशु चिकित्सा सेवा और एकीकृत मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से इस 'इससे जुड़े सेक्टर' को मजबूत करता है। इन क़दमों से उत्पादकता बढ़ाने, नुकसान कम करने और किसानों के लिए बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

- **मछली पालन और ग्रामीण रोज़गार**

2026-27 के बजट में ग्रामीण आमदनी में विविधता लाने के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा दांव लगाया गया है। एक मुख्य क़दम 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास है, जिससे इन पानी की जगहों को एक्वाकल्चर वैल्यू चेन के हब में बदला जा सके। स्टार्टअप और फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को आपस में जोड़ करके, सरकार का मकसद ग्रामीण मछली पालन और शहरी खपत के बीच के अंतर को कम करना है।

एक और जरूरी पॉलिसी लीवर जो शुरू किया गया है, वह है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में भारतीय झंडे वाले जहाजों से पकड़ी गई मछली के लिए ड्यूटी-फ्री स्टेटस। इस क़दम से वैश्विक बाज़ार में भारतीय सीफूड की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा।

- **भंडारण और मूल्य श्रृंखला में निवेश**

खेती में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान और कमजोर मार्केट लिंकेज रहे हैं। बजट

भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य श्रृंखला के विकास पर फोकस करके इस मुद्दे को सुलझाता है। नारियल के बागानों को फिर से ठीक करने और नए बाग लगाने के लिए भी मदद की घोषणा की गई है। पुराने और बेकार नारियल के पेड़ों को बेहतर किस्मों से बदला जाएगा ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके।

इसी तरह, 2030 तक कच्चे काजू और कोको के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसका लक्ष्य है कि बेहतर प्रसंस्करण और निर्यात संपर्क द्वारा 'इंडियन काजू' और 'इंडियन कोको' को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जाए।

### गरीब

आर्थिक वृद्धि, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अपनी चमक खो देती है अगर उसका फ़ायदा समाज के हाशिये पर रहने वालों तक नहीं पहुंच पाता। पिछले दस सालों में, भारत ने कई तरह की गरीबी कम करने और रहने की स्थिति को बेहतर बनाने में काफ़ी तरक्की की है।

समावेशी विकास केंद्रीय बजट 2026-27 का एक मुख्य विषय बना हुआ है। इस चौथे स्तंभ के लिए रणनीति दो तरह की हैः पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करना और साथ ही औपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए रास्ते बनाना।

हालांकि ग्रामीण आवास, पोषण कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा इस कोशिश का आधार बने हुए हैं, लेकिन अब इन्हें कौशल प्रशिक्षण और सूक्ष्म उद्यम विकास में दखल के साथ जोड़ा गया है। इस दिशा में जरूरी पहल इस तरह हैं:

- **वीबी-जी राम जी: ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना**

इस स्तंभ के तहत सबसे जरूरी घोषणाओं में से एक है वीबी-जी राम जी यानी विकसित भारत - रोज़गार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण)। यह प्रोग्राम पहले के ग्रामीण रोज़गार के फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाकर उसका विस्तार करता है, ताकि आय सुरक्षा बेहतर हो और गांवों में रोज़गार के ज़्यादा अवसर तैयार हो सके सकें।

यह स्कीम 125 दिनों तक की गारंटी वाले ग्रामीण रोज़गार, बेरोज़गारी में मदद, साथ ही ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी बचाने और रोज़गार से जुड़ी गतिविधियों से पूरी परियोजनाओं के लिए मदद का वादा करती है।

- **गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा**

यह पक्का करना कि कोई भी परिवार भूखा न रहे, एक मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है। बजट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को लगातार समर्थन देकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है। यह स्कीम योग्य लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम मुफ़्त अनाज देकर महंगाई और पोषण की कमी को दूर करने में एक अहम उपाय का काम करती रहती है।

- **पोषण योजना**

बजट ने पोषण और ख़ासकर आंगनवाड़ी सेवा और चाइल्डकेयर पहल के माध्यम से बाल विकास कार्यक्रम को और मज़बूत किया है। ये कार्यक्रम मां और बच्चे के स्वास्थ्य, शुरुआती पढ़ाई और पोषण के नतीजों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

- **गरीबों के लिए घर**

कम आय वाले परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षित घर तक पहुंच प्रदान करना एक और ज़रूरी क़दम है। इससे स्वास्थ्य और सफ़ाई भी बेहतर होती है, और सम्मान तथा सुरक्षा का एहसास होता है। बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में सस्ते घरों के लिए काफ़ी फ़ंडिंग दी गई है। ग्रामीण घरों के लिए आवंटन में 69 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जबकि शहरी घरों में 179 प्रतिशत की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

किसी देश की तरक्की सिर्फ़ उसके विकास की रफ़्तार से नहीं, बल्कि उस दिशा से भी तय होती है जिसमें वह चलायमान है। केंद्रीय बजट 2026-27 युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को अपने विजन के केंद्र में रखकर वह दिशा देने की कोशिश करता है। ऐसा करते हुए, यह मानता है कि विकास बड़े पैमाने पर और समावेशी होना चाहिए, जो समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

इंसानी काबिलियत, ग्रामीण बदलाव, सामाजिक सुरक्षा और उद्यमों में निवेश के ज़रिए, केंद्रीय बजट 2026-27 एक विकसित भारत के लिए एक साफ़ रोडमैप देता है। यह सही मायने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को भी दिखाता है। ❑

(सह-लेखिका, ईशा खोसला, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की निदेशक हैं। ईमेलः isha.khosla@nic.in)